Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

विशेषांक

कमल संदेश

वर्ष-19, अंक-06 16-31 मार्च, 2024 (पाक्षिक) ₹20

हमारा संकल्प 'विकसित भारत'

भारत मंडपम (नई दिल्ली) में 17 फरवरी, 2024 को भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं श्री अमित शाह

पोखरण (राजस्थान) में 12 मार्च, 2024 को ट्राई-सर्विस फायरिंग एवं युद्धाभ्यास कार्यक्रम 'भारत शक्ति' के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा

भारत मंडपम (नई दिल्ली) में 24 फरवरी, 2024 को सहकारी क्षेत्र के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल एवं श्री अर्जुन मुंडा

संसद भवन (नई दिल्ली) में 21 सितंबर, 2023 को महिला संसद सदस्यों के साथ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के पारित होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वाराणसी में 23 सितंबर, 2023 को भारत की अमृत-पीढ़ी के साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 10 सितंबर, 2023 को जी20 प्रतिनिधिमंडल के साथ राजघाट का दौरा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

1. गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान 06
2. किसानों का कल्याण सुनिश्चित 10
3. नारी शक्ति – महिलाओं के नेतृत्व में विकास 14
4. भारत की अमृत-पीढ़ी हो रही सशक्त 19
5. मध्यम वर्ग का जीवन आसान 24
6. सभी के लिए सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवा 28
7. 'राष्ट्र प्रथम' विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा 32
8. भारत, वैश्विक आर्थिक महाशक्ति 36
9. व्यापार सुगमता 40
10. इन्फ्रास्ट्रक्चर – प्रगति पथ 42
11. भारत का टेक्नोलॉजी युग 48
12. नॉर्थ-ईस्ट : विकास का नया इंजन 53
13. विरासत और विकास 56
14. पर्यावरण और सतत विकास 62

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

बड़े लक्ष्यों को लेकर चल रहा आज का भारत प्रगति की तेज गति से समझौता नहीं कर सकता।

(11 मार्च, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा

जब भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का कार्यक्रम चलाया तब कांग्रेस इसका उपहास करती थी! हमने सदैव कहा है कि जब अंतिम व्यक्ति का उदय होगा, तभी भारत का उदय होगा।

(7 मार्च, 2024)

अमित शाह

मोदी जी के पास बीते 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और आने वाले 25 साल का विजन है।

(14 मार्च, 2024)

राजनाथ सिंह

हम लोगों ने CAA (Citizen Amendment Act), नागरिकता संशोधन कानून लागू किया और यह कानून किसी की भी नागरिकता को समाप्त करने वाला कानून नहीं है, बल्कि यह तो नागरिकता देने वाला कानून है।

(14 मार्च, 2024)

बी.एल. संतोष

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्री शंकराचार्य हिल्स को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो या पंजाब या तमिलनाडु या केरल या उत्तर पूर्व, 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र पूरे देश को एक साथ जोड़ रहा है।

(07 मार्च, 2024)

निर्मला सीतारमण

2005-06 के बाद से भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो 2013-14 के 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत हो गई है, इसमें 17.89 प्रतिशत की कमी आयी है। परिणामस्वरूप पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आये हैं।

(15 जनवरी, 2024)

'अबकी बार, 400 पार'

जैसे-जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, 'अबकी बार, 400 पार' का नारा पूरे देश में गूंजने लगा है। यह परिदृश्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं दूरदर्शी नेतृत्व एवं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जन-जन के निरंतर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनता का अपार विश्वास इसी बात से परिलक्षित होता है कि आज लोग 'मोदी की गारंटी' को 'गारंटी पूरी होने की गारंटी' मानते हैं। जहां 'विकसित भारत' के निर्माण का प्रधानमंत्री मोदीजी का संकल्प अब पूरे देश का संकल्प बन गया है; असीमित उत्साह एवं नया आत्मविश्वास तथा जोश से भरे लोग इस लक्ष्य की ओर मजबूती से चल पड़े हैं। देश में मानो एक नया सवेरा हुआ है, लोगों के आंखों में एक विकसित, सुदृढ़ एवं उज्ज्वल भारत का स्वप्न है। आज जब जनता का आशीर्वाद भाजपा पर बरस रहा है तब चुनाव जैसे अवसर पर मतदान कर लोग 'विकसित भारत' के लक्ष्यों के प्रति स्वयं को पुनर्समर्पित कर रहे हैं।

पिछले दस वर्षों की अविस्मरणीय उपलब्धियां, जिससे आज सभी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ एवं एजेंसियां चमत्कृत हैं, विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ कर रही हैं

पिछले दस वर्षों की अविस्मरणीय उपलब्धियां, जिससे आज सभी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ एवं एजेंसियां चमत्कृत हैं, विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ कर रही हैं। 'फ्रैजाइल फाइव' से 'फैबुलस फाइव' की यात्रा 'रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांस्फॉर्म' की यात्रा रही है जिससे देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कांग्रेसनीत यूपीए के दस वर्षों के कुशासन, व्यापक भ्रष्टाचार, जनता के खजाने की लूट, भारी महंगाई, खाली होता विदेशी मुद्रा भंडार और लुढ़कती विकास दर के संदर्भ में यदि देखें तो पिछले दस वर्ष की यात्रा चमत्कारी लगती है। कांग्रेसनीत यूपीए का कार्यकाल 'पॉलिसी पैरालासिस' के दौर के रूप में जाना जाता है तथा 2004-2014 के इस दशक को 'लॉस्ट डिकेड', खोया हुआ दशक भी कहा जाता है। कांग्रेसनीत यूपीए के कुशासन में पूरा देश नकारात्मकता एवं निराशा के दलदल में डूब गया था और देश हर क्षेत्र में पिछड़ रहा था। कोई भी इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता कि देश को इस दलदल से निकालने की चुनौती बहुत ही विकट थी और दुनियाभर के विशेषज्ञ कहने लगे थे कि भारत के भविष्य की संभावनाओं पर अब प्रश्नचिन्ह लग गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जो पूरे देश के लिए आशा की किरण के रूप में उभरे हैं, उन्होंने न केवल देश को इस दलदल से निकाला, बल्कि अपने परिवर्तनकारी निर्णयों से उन ऊंचाइयों पर ले गए जहां से 'विकसित भारत' का स्वप्न अब साकार होता संभव दिख रहा है।

पिछले दस वर्षों में देश में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिससे जहां कई जनाकांक्षाएं पूर्ण हुई हैं वहीं कई नई जनाकांक्षाएं उभरी भी हैं। आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूरे देश को बड़ा सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन्होंने वैश्विक मंचों पर मानवता की सेवा का व्रत लिए हुए भारत का 'विश्वमित्र' के रूप में नेतृत्व किया है। हर देश के साथ उनकी जरूरत के समय खड़ा रहकर भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं अन्य कई आपदाओं के समय सभी देशों की हरसंभव सहायता की है। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान देकर समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित एवं उपेक्षित वर्गों का अभिनव योजनाओं एवं कल्याणकारी कदमों से सशक्तीकरण हुआ है। यह पहली बार है कि भारत की गौरवशाली विरासत का विश्वभर में उत्सव मनाया गया है और हर भारतीय अपनी अद्वितीय विरासत को लेकर गौरवान्वित है। 'विकास' शब्द अब मंत्र बन गया है तथा सारा देश एक नई ऊर्जा की अनुभूति कर रहा है। अब देश नए क्षितिजों को छूना चाहता है, जो कुछ असंभव लगता था, उसको संभव करना चाहता है।

आज जब 'नया भारत' अपने उज्ज्वल भविष्य को लेकर आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा हे, कमल संदेश का यह विशेषांक अपने सुधी पाठकों के लिए प्रकाशित किया गया है। हमें आशा है कि हमारे पाठकगण न केवल मोदी सरकार की पिछले दस वर्षों की चमत्कारिक उपलब्धियों को इस विशेषांक में पढ़ पाएंगे, बल्कि अन्य पाठकों को पढ़ाएंगे भी, ताकि 'विकसित भारत' का संदेश घर-घर पहुंचे। आपके निरंतर सहयोग एवं उत्साहवर्धन के लिए हम आपके सदा आभारी हैं। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

गरीबों की सेवा वंचितों का सम्मान

“डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना हों, इन सभी ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है।”

– **नरेन्द्र मोदी**

गरीब कल्याण, देश का कल्याण

- गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
- 80 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित
- जन धन योजना–वित्तीय समावेशन की विश्व में सबसे बड़ी पहल
- कमजोर वर्गों की आकांक्षाओं की पूर्ति और उनके अधिकारों की रक्षा
- दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण
- जनजातीय लोगों के लिए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित
- 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण गरीबों को सभी बुनियादी सुविधाओं वाले आवास उपलब्ध

जनजातीय लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित

- 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया गया
- 401 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को शुरू किया गया
- 3,958 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना; 11.83 लाख आदिवासी लोग जुड़े

दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण

- दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया
- सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण क्रमशः 3% से बढ़ाकर 4% और 3% से बढ़ाकर 5% किया गया
- 25.94 लाख दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 14,175 शिविरों में सहायता और सहायक उपकरण बांटे गए

कमजोर वर्ग

आकांक्षाओं की पूर्ति

- ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण
- राज्यों को खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार

पीएम स्वनिधि - रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए आसान ऋण

- कोविड–19 महामारी के दौरान रेहड़ी–पटरी वालों को गिरवी मुक्त कर्ज की सुविधा दी गई
- पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक रेहड़ी–पटरी वालों को मिला ऋण

पीएम विश्वकर्मा योजना

- पीएम विश्वकर्मा 13 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना
- बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण; पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत 18 पारंपरिक शिल्पकलाएं शामिल
- विश्वकर्मा भाई–बहनों को 3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी ऋण
- 15 हज़ार रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन, कौशल उन्नयन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता

दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल

- 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते
- लाभार्थियों के बैंक खातों में 32.29 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 2.73 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित बचत (मार्च, 2022 तक)

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक

- पिछले 9 वर्षों के दौरान 25 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले
- गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत हो गया
- भारत के 2030 से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करना) हासिल करने की संभावना

80 करोड़ भारतीयों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

- 1,424 लाख मीट्रिक टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत वितरित किया गया (अप्रैल, 2020 – अक्टूबर, 2023)
- एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड से देश भर में लोगों को आसानी से मिल रहा राशन
- 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन का मासिक औसत

किसानों का कल्याण सुनिश्चित

"किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।"

– नरेन्द्र मोदी

पीएम किसान

- 2019 में शुरुआत, किसानों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6 हजार रुपये
- पहली बार पूरे देश में शुरू किया गया प्रत्यक्ष नकद समर्थन
- पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 11.8 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

- 2016 में शुरुआत, फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता
- 49.5 करोड़ किसान आवेदकों का पंजीकरण, पिछले 7 वर्षों में 14.9 करोड़ से अधिक आवेदकों को 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावे हुए प्राप्त
- पंजीकृत किसानों में 84 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान

फसल बीमा योजना 2014-15 बनाम 2022-23

बीमित आवेदनों में 3.19 गुना वृद्धि	गैर ऋण वाले किसानों के हिस्से में 7.2 गुना वृद्धि	प्रति हेक्टेयर औसत बीमा राशि में 2.36 गुना वृद्धि
3.70 करोड़ से बढ़कर 11.81 करोड़ हुई	5.4 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हुए	18,000 रुपये से बढ़कर 42,531 रुपये हुई

एमएसपी में गुणात्मक वृद्धि 2013-14 से 2023-24

एमएसपी (2013-14) रु/क्विंटल		एमएसपी रु/क्विंटल		% बढ़ोतरी
चावल	₹1310	चावल (2023-24)	₹ 2183	67%
गेहूँ	₹1400	गेहूँ (2023-24)	₹ 2275	62.5%

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- मृदा में पोषक तत्वों के उपयोग में वृद्धि के लिए 2014-15 में योजना की शुरुआत
- किसानों को 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किए गए जारी

ई-नाम: मौजूदा बाजारों को ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत करने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया

अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष

मोटे अनाज के महत्व को पहचान कर लोगों को पोषक भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने और स्वदेशी व वैश्विक मांग का सृजन करने के क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और मार्च 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित कर दिया।

सहकारी क्षेत्र में सुधार

- पिछले 25–30 वर्षों से सहकारी क्षेत्र में एक ठहराव देखने को मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है।
- श्री मोदी ने चीनी मिलों के लंबित 15,000 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद का समाधान किया है।
- मोदी सरकार संवैधानिक दायरे में सहकारी कानून में एकरूपता लाने के लिए काम कर रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

- एक विशेष अभियान के तहत सभी पीएम–किसान लाभार्थी केसीसी के माध्यम से कवर
- 8.85 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण–सुविधा के साथ 7.34 करोड़ से अधिक केसीसी आवेदन स्वीकृत किये गए (31 मार्च, 2023 तक)

पीएम-प्रणाम

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में 'पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड ऐमेलिओरेशन ऑफ मदर अर्थ (पीएम–प्रणाम)' को मंजूरी दी।
- इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है।

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मैपिंग)

- अप्रैल, 2020 में हुई शुरुआत
- ग्रामीण इलाकों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित करने का उद्देश्य
- अब तक 1.6 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कार्ड बनाए गए

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

- उद्देश्य – ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत के स्तर पर जल उपयोग में दक्षता बढ़ाना
- 2015-16 से 78 लाख हेक्टेयर कवर
- नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया
- 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपये आवंटित

कृषि अवसंरचना कोष

- कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा
- योजना के कार्यान्वयन के 3 साल से भी कम समय में 38,326 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसने कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 30,030 करोड़ रुपये के कुल ऋण के साथ 50,988 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
- कृषि इन्फ्रा परियोजनाओं ने 5.8 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जबकि सालाना 3.7 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 46.3 लाख मीट्रिक टन बागवानी संबंधी उत्पादन की बचत की है और किसानों को 20-25% की सीमा तक बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित की है।

नारी शक्ति
महिलाओं के नेतृत्व में विकास

“आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति–निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।”

- नरेन्द्र मोदी

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था
- इस अधिनियम से भारत ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम।
- आरक्षित कोटे के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण।
- यह अधिनियम लैंगिक समानता और समावेशी समाज के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह कानून महिला नेतृत्व को बढ़ावा देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

उज्ज्वला योजना

तब

2014

14.52 करोड़

घरों में एलपीजी कनेक्शन

अब

2023

31.54 करोड़

घरों में एलपीजी कनेक्शन

वित्त वर्ष 2023-24 से अगले तीन वर्षों में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन दिए जायेंगे, जिससे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ होगी

भारत में एल पी जी कवरेज

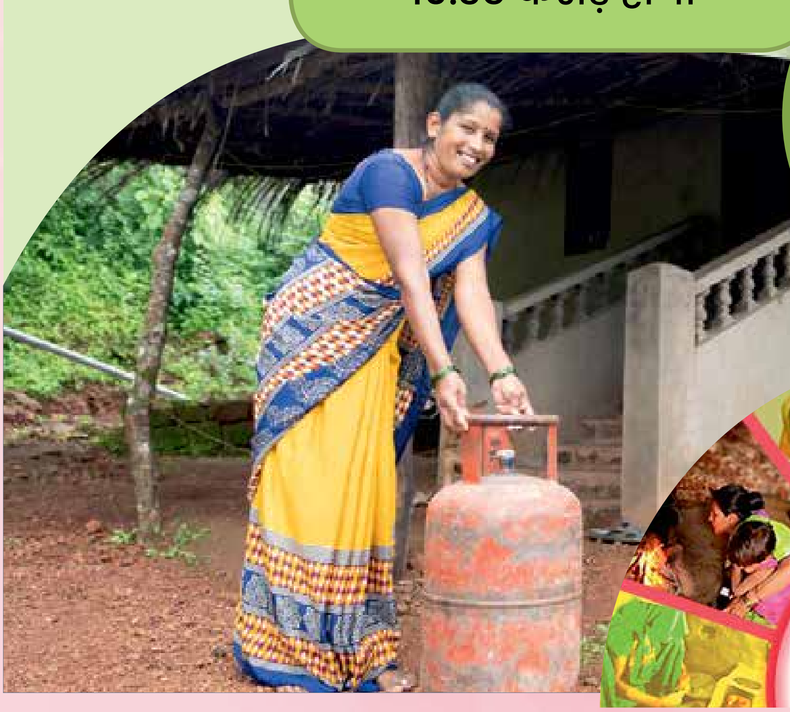

सख्त कानून

- तीन तलाक़ का अपराधीकरण
- मुस्लिम महिला की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित
- तीन तलाक के मामलों में उल्लेखनीय कमी

महिलाओं के लिए प्रमुख योजनाएं

महिलाओं के लिए **28 करोड़ जन-धन खाते**

स्टार्ट-अप इंडिया: 47% स्टार्ट-अप में कम से कम 1 महिला निदेशक

पीएम मुद्रा के अंतर्गत 69% से अधिक खाताधारी महिला उद्यमी

स्टैंड अप इंडिया के तहत 81% महिला उद्यमी

महिलाओं का जीवन बना आसान

- 2019 में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास था नल कनेक्शन
- जल जीवन मिशन के तहत अक्टूबर, 2023 तक 10 करोड़ से अधिक नये परिवारों को मिला नल से जल

महिला हेल्पलाइन

- 1 अप्रैल, 2015 को महिला हेल्पलाइन 181 शुरू की गई जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल के जरिए 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करती है

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

- पीएमएमवीवाई के तहत 3.11 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 14,103 करोड़ रुपये वितरित

महिलाओं के जीवन में सुधार

गरिमा

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.74 करोड़ शौचालय

पीएमएवाई-जी के तहत बने 2.5 करोड़ से अधिक घरों में से 70% की अकेले या संयुक्त रूप से मालिक हैं महिलाएं

तीन तलाक को गैर-कानूनी किया

जीवन सुगमता

10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शनों से महिलाओं को धुएं से मिली मुक्ति

मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह

जल जीवन मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक नये परिवारों को मिला 'नल से जल'

उद्यमिता

जनधन खातों के द्वारा 28 करोड़ महिलाएं बैंकों से जुड़ीं

स्टैंड अप इंडिया के तहत 79% उद्यमी महिलाएं हैं

मुद्रा योजना के तहत 69% से अधिक खाता धारक महिला उद्यमी

भारत की अमृत-पीढ़ी हो रही सशक्त

"विकसित भारत के विज़न को लेकर देश की अमृतयात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं।"

– नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

- परिवर्तनकारी सुधार: 1986 की 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव

  निष्ठा शिक्षकों की समग्र शिक्षा

  विद्यांजलि वॉलंटियर आधारित मार्गदर्शन

  लचीला पाठ्यक्रम विषयों के रचनात्मक संयोजन के साथ, एकाधिक प्रवेश/निकास के विकल्प

  क्रेडिट का एकेडमिक बैंक शैक्षणिक अंकों को डिजिटली स्टोर करना

  निपुण भारत आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता
- 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों में से चयनित 6,207 स्कूलों को पहली किस्त के रूप में कुल 630 करोड़ रुपये जारी
- 7 अगस्त, 2023, तक 12 संस्थानों को 'उत्कृष्ट संस्थान' (आईओई) के रूप में अधिसूचित किया गया

स्किल इंडिया मिशन

पीएम कौशल विकास योजना

युवाओं को **नि:शुल्क** कौशल प्रशिक्षण

1.38 करोड़ युवा प्रशिक्षित

54.27 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को किया गया अपस्किल और रीस्किल

औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (आईटीआई) में 1.5 गुना की बढ़ोतरी

- भारी उपक्रम मंत्रालय ने उद्योग 4.0 में जागरूकता और कौशल, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यबल को बढ़ाने के लिए 4 समर्थ उद्योग केंद्रों के माध्यम से क्षमता निर्माण की पहल शुरू की
- जुलाई, 2023 तक 7.26 लाख उम्मीदवारों को 288 जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया
- ज़ांज़ीबार (तंजानिया) और अबू धाबी (यूएई) में आईआईटी के नए परिसरों की स्थापना से उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत

शिक्षा का बुनियादी ढांचा

	2014	2023
IIT	16	23
IIIT	9	25
IIM	13	20
AIIMS	8	23

2013-14 के बाद से कुल खर्च हुआ दोगुना

(शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त व्यय)
(लाख करोड़ रुपये में)

2014 के बाद से लगभग 390 विश्वविद्यालय स्थापित

2013-14	2022-23
723	1113

वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा

देश में अटल टिंकरिंग लैबों की संख्या **10,000** से अधिक

ये 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 722 जिलों में फैले हुए हैं

स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS), स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम (SISFS) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSI) जैसी योजनाएं

खेलो इंडिया

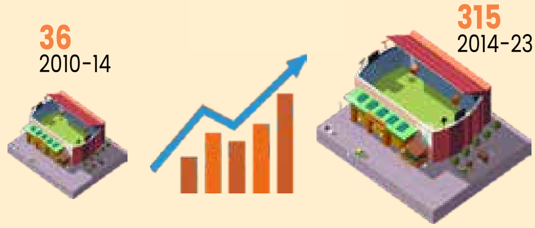

देश में खेलों का बुनियादी ढांचा

- **मणिपुर में 643.34 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत से देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा**

खेल प्रतिस्पर्धाओं में चमकता भारत

हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 107 और एशियाई पैरा खेलों में 111 से अधिक पदक हासिल किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेल 2022 में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात की

एक भारत श्रेष्ठ भारत

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के साथ भारत अनेकता में एकता को मना रहा है

"'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने और संवाद बढ़ाने का एक प्रयास है।"

– नरेन्द्र मोदी

मध्यम वर्ग का जीवन आसान

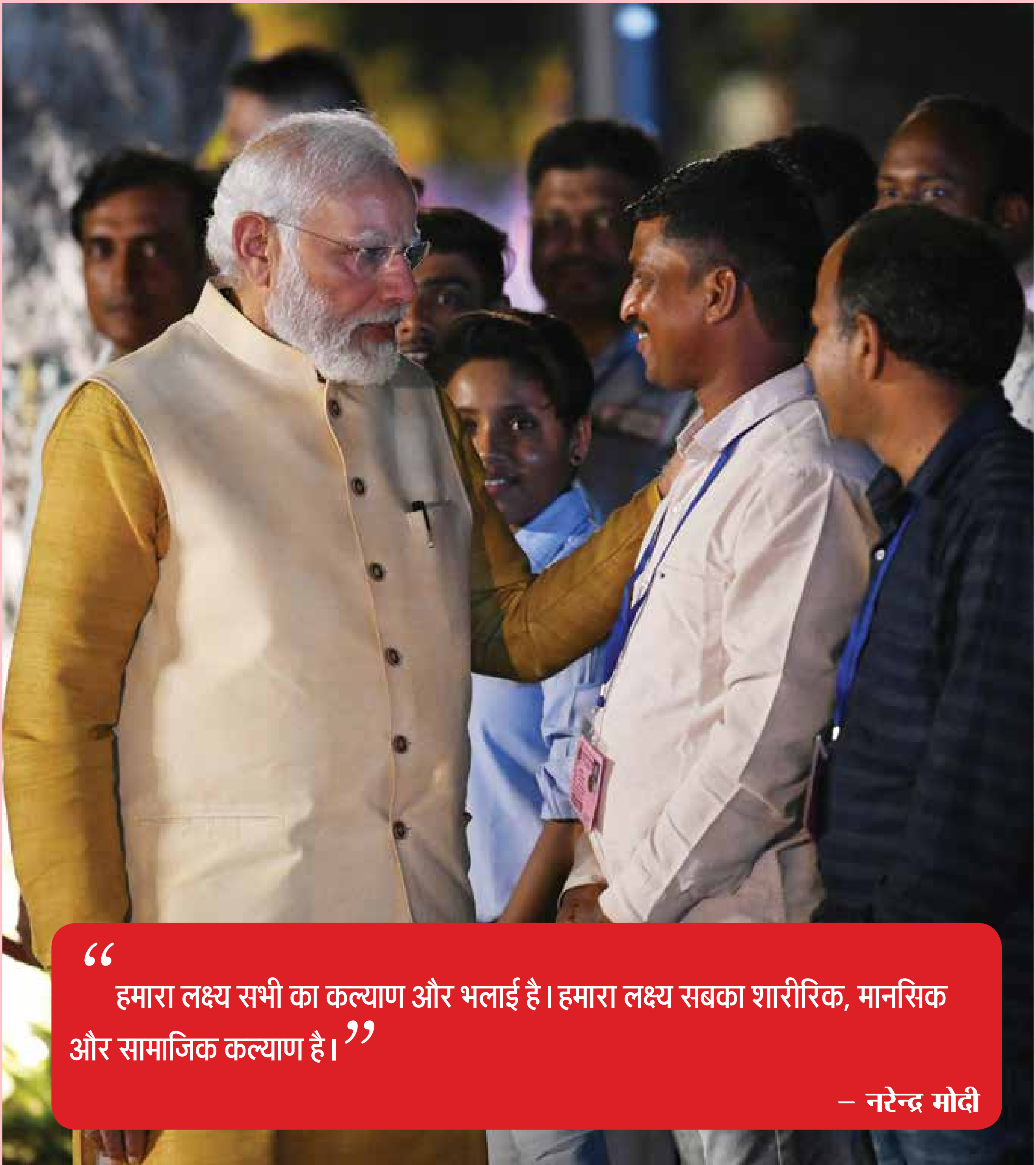

"हमारा लक्ष्य सभी का कल्याण और भलाई है। हमारा लक्ष्य सबका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है।"

– नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

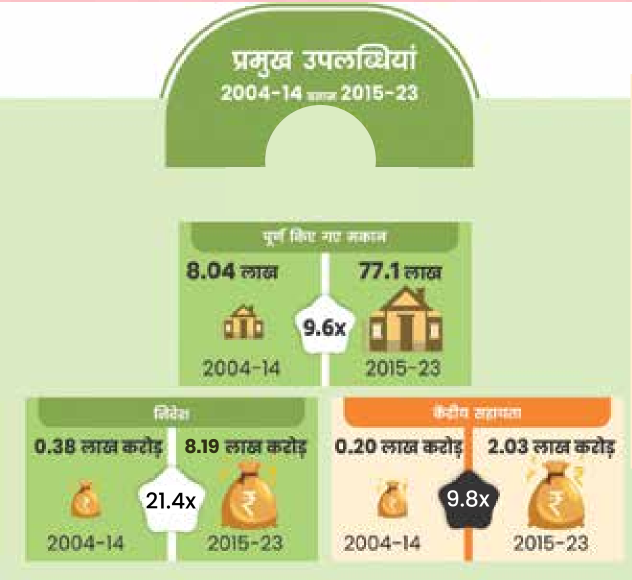

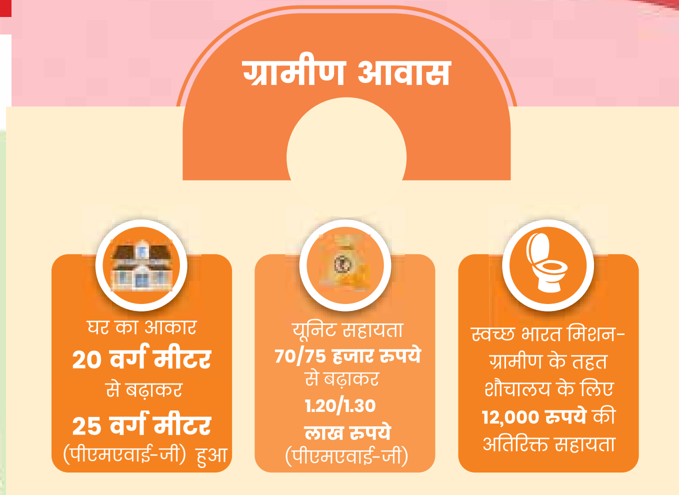

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

- शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और शहर के ठोस कचरे का शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य
- 20 करोड़ से अधिक नागरिक सीधे तौर पर जुड़े; 67.13 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6.52 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
- 4,884 शहर व कस्बे 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- वर्ष 2016 में शुभारंभ
- ग्रामीण लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाते हैं
- 2.5 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा

'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ'

देशभर में 8.75 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण पेश करते हुए 1 अक्तूबर, 2023 को 'स्वच्छता के लिए श्रमदान' किया।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य ठोस और तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से गांवो की ओडीएफ़ स्थिति को बनाए रखना हैं।
- 4.61 लाख से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया।
- महिला स्वयं सहायता समूह भी प्लास्टिक कचरे प्रबंधन का कार्य संभाल रही हैं, जिससे आय सृजन के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

- जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराकर लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने का लक्ष्य
- 1.72 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किए गए; 1.35 करोड़ सीवरेज कनेक्शन दिए गए
- 3,340 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले सीवरेज शोधन संयंत्र जोड़े गए
- 2,525 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और लगभग 4,603 एकड़ हरित क्षेत्र एवं पार्क विकसित किए गए

हर घर जल

- अगस्त 2019 में शुभारंभ, जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराना
- पानी समितियां; जन आंदोलन; समुदाय का स्वामित्व और महिलाओं की केंद्रीय भूमिका

2019 से पहले **3.23 करोड़** परिवारों को नल से जल आपूर्ति की सुविधा थी

अक्तूबर, 2023 तक **13.52 करोड़** परिवारों के पास है नल से जल का कनेक्शन

रोजगार मेला

- 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान। अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है।
- सितम्बर, 2017 से जुलाई, 2023 के बीच 5.5 करोड़ नए ईपीएफओ ग्राहक जुड़े

सौभाग्य योजना

सभी के लिए सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवा

“हमने तय किया कि किसी भी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज टालना न पड़े। हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हमारे गरीब परिवारों को भी उनके घरों के पास बेहतर इलाज मिले।”

– **नरेन्द्र मोदी**

आयुष्मान भारत

विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना

- प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक लाभ का कवरेज
- 12 करोड़ गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा
- 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी
- 5.7 करोड़ से अधिक लोगों का हुआ मुफ्त इलाज
- 2.21 लाख निजी अस्पतालों की भी सक्रिय भागीदारी

आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एबी-एचडब्ल्यूसी)

- 1.61 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित
- विभिन्न बीमारियों की 141.5 करोड़ से अधिक जांचें
- 14.36 करोड़ से अधिक टेलीपरामर्श आयोजित किए गए

पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन

- 25 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के निर्माण एवं उन्नयन की सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना
- वित्तीय वर्ष 2021–22 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025–26 तक की अवधि में 64,180 करोड़ रुपये की कुल लागत

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)

- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 27 सितंबर, 2021 को किया गया शुभारंभ
- 48 करोड़ से अधिक आभा (एबीएचए) नंबर और 2.39 लाख स्वास्थ्यकर्मी पंजीकृत
- 2.22 लाख से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं (सरकारी या निजी क्षेत्र के अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों, क्लीनिकों आदि सहित) शामिल

'आयुष्मान भव' अभियान

- एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की संतृप्ति कवरेज प्रदान करना है

ई-संजीवनी ओपीडी

- 1.05 करोड़ से अधिक ई–संजीवनी ओपीडी परामर्श दिए गए

अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार

23 फरवरी, 2024 को एम्स बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में नई सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

- 15 नए एम्स और 319 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए।
- वर्ष 2014 से 2023 के बीच एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1.08 लाख हुई। साथ ही स्नातकोत्तर पीजी सीटों की संख्या 31,185 से बढ़कर 70,000 से अधिक हुई।

अंगदान से जीवनदान

- अंगदान को आसान बनाने के उद्देश्य से NOTTO की वेबसाइट पर नागरिकों के लिए अंगदान का संकल्प दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध
- 2014 में सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर की अवधारणा पेश की, जो एम्बुलेंस के लिए ख़ाली कराया गया सीमांकित विशेष सड़क मार्ग है। ये प्रतिरोपण के लिए प्राप्त अंगों को गंतव्य अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
- 2013 में देश में पांच हज़ार से कम अंगदान हुए थे, लेकिन 2022 में यह संख्या 15 हज़ार से अधिक

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

- देशभर में 10,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर मिल रही सस्ती दरों पर अच्छी दवाइयां
- जन औषधि केंद्रों में 1965 प्रकार की दवाएं और 293 अन्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध
- इन केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% कम दाम पर उपलब्ध

कोविड-19 टीकाकरण अभियान

- टीके की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
- को-विन द्वारा अब तक 102.74 करोड़ से अधिक पहली डोज के प्रमाण पत्र, 95.21 करोड़ से अधिक दूसरी डोज के प्रमाण पत्र और 22.87 करोड़ से अधिक प्रिकॉशनरी डोज के प्रमाण पत्र जारी
- दुर्गम इलाकों में कोविड-19 के टीकों की ड्रोन आधारित आपूर्ति

मादक पदार्थ के आदी लोगों का पुनर्वास

- नशा मुक्त भारत अभियान युवाओं को नशीली पदार्थों के प्रयोग के प्रति जागरूक करने के लिए शुरू किया गया
- 10.6+ करोड़ लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे देश में जागरूक किया गया
- देश भर में 638 सरकार समर्थित परामर्श केंद्र, उपचार और नशामुक्ति सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिन तक आसानी से पहुंच के लिए जियो-टैगिंग भी की गयी है
- नशा करने वालों को प्राथमिक परामर्श प्रदान करने के लिए '14446' राष्ट्रीय नशामुक्ति टोल हेल्पलाइन शुरू की गई

'14446'

राष्ट्रीय नशा मुक्ति टोल हेल्पलाइन

बाल स्वास्थ्य एवं पोषण

मिशन इन्द्रधनुष

- मिशन इंद्रधनुष (एमआई) का उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाकर बच्चों का पूर्ण टीकाकरण तथा गर्भवती महिलाओं के बीच इस कवरेज को 90% करना और उसके बाद इसे निरंतर बनाए रखना है।
- मई, 2022 तक 4.45 करोड़ बच्चों और 1.2 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण।

'राष्ट्र प्रथम' विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा

"हमें दुनिया के हर वर्ग, हर देश, हर समाज, हर रीजन को जोड़ना होगा। और यही एक परिवार की भावना है।" – **नरेन्द्र मोदी**

जी 20 शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली की सफलता

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जनभागीदारी के दृष्टिकोण ने जी–20 कार्यक्रमों और गतिविधियों में हमारे समाज के व्यापक वर्गों को शामिल किया।
- 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकों ने जी–20 आयोजन के लिए एक अभूतपूर्व माहौल पैदा किया। परिणामस्वरूप, भारत की जी–20 अध्यक्षता वास्तव में जन–केंद्रित थी और एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उभरी।
- नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने भारत की समकालीन प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ–साथ हमारी विरासत, संस्कृति और परंपराओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया। जी–20 सदस्य देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने इसकी व्यापक सराहना की।
- शिखर सम्मेलन के दौरान भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा समझौते और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का निष्कर्ष महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे।

हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर

स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH) को 'प्रचंड' नाम दिया गया है, जिसे भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है।

LCH दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलिकॉप्टर है, जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के अच्छे–खासे भार के साथ उड़ान भर सकता है और उतर सकता है।

नागरिकों को मिला सुरक्षित माहौल

देश में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं

उग्रवाद और नक्सलवाद

- उग्रवाद जनित हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी (2014 में 824 की तुलना में 2022 में 201 घटनाएं)
- सिविलियन और सेक्योरिटी फोर्स की मौतों में 96% की कमी (2014 में 232 की तुलना में 2022 में 09 मौतें)

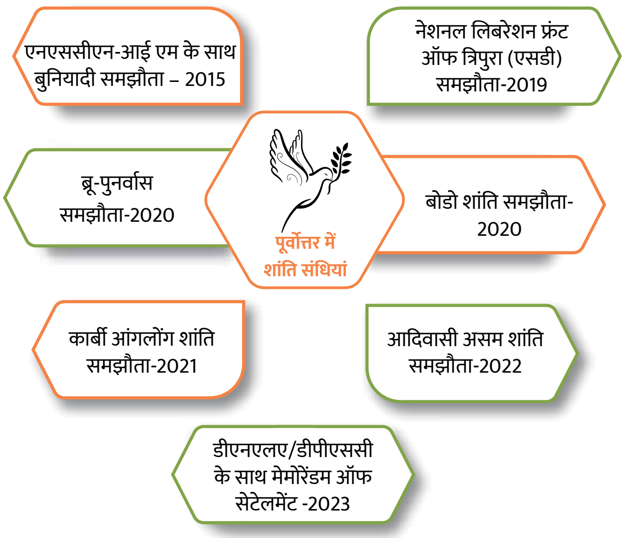

ऑपरेशन अजय

- इजरायल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने शुरू किया 'ऑपरेशन अजय'
- स्थिति पर नजर रखने और सूचना एवं सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित

ऑपरेशन गंगा

- 23,000 भारतीयों को यूक्रेन से सफलतापूर्वक वापस लाया गया
- 18 देशों के 147 नागरिकों को भी बाहर निकाला गया
- 90 टन राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई

ऑपरेशन कावेरी

- युद्धग्रस्त सूडान से 3,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया
- एयरपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं क्वारेंटाइन सेंटर्स में नि:शुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था

ऑपरेशन दोस्त

- भारतीय सेना के क्षेत्रीय अस्पताल ने भूकंप प्रभावित तुर्की के हरेय प्रांत में 3,600 से अधिक लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई
- इलाज के लिए आए मरीजों की लगभग 1,200 लैब जांचें की गईं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में तुर्की और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त' में शामिल एनडीआरएफ कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए

आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण

कानून संबंधी विषय

- 890 केंद्रीय कानून लागू; 205 राज्य कानून रद्द किए गए; 130 राज्य कानून संशोधित और लागू; आरक्षण लाभ का विस्तार

विकास संबंधी विषय

- पीएमडीपी का तेज क्रियान्वयन, जम्मू-कश्मीर में 58,477 करोड़ रुपये की लागत से 53 पीएमडीपी परियोजनाओं पर कार्य जारी। लद्दाख में 21,441 करोड़ रुपये की लागत की 9 परियोजनाओं पर कार्य जारी। जम्मू-कश्मीर में 32 परियोजनाओं व लद्दाख में तीन परियोजनाओं के कार्य पूर्णत:/आंशिक रूप से पूरे।
- जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत 28,400 करोड़ रुपये के कार्यों की शुरुआत। इससे पूंजी निवेश, पूंजीगत ब्याज सबवेंशन, जीएसटी से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

अग्निपथ योजना

- अग्निपथ सशस्त्र बलों के लिए एक परिवर्तनकारी योजना है, जो भारतीय सेना को युवा शक्ति, उच्च तकनीक से लैस और अति-आधुनिक दृष्टिकोण के साथ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सैन्य बल बनाने की दिशा में कार्य करने जा रही है।
- सरकार ने 15 जून, 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में चार साल की अवधि के लिए देश तीनों सेनाओं के 'अधिकारी के रैंक से नीचे' कैडर में भर्ती किया गया।
- 17.5 से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक

- इन्सर्जन्सी के विरुद्ध अभियान, म्यांमार- 9 जून, 2015
- सर्जिकल स्ट्राइक, पीओके- 28-29 सितंबर, 2016
- बालाकोट हवाई हमला- 26 फरवरी 2019

भारत
वैश्विक आर्थिक महाशक्ति

"ये दशक और आने वाले 25 साल भारत को लेकर अभूतपूर्व विश्वास के हैं। सबके प्रयास से ही भारत अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करेगा।"

– **नरेन्द्र मोदी**

वैश्विक महामारी के बावजूद सबसे तेज वृद्धि

- भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना
- 2024 में 7.6% की अनुमानित विकास दर के साथ भारत के लिए मजबूत विकास संभावनाएं, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक बनाती है।
- निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि और खपत में उछाल के कारण आर्थिक गतिविधियों में सुधार

जीएसटी: एक राष्ट्र, एक कर

- 1 जुलाई, 2017 को लॉन्च: जीएसटी में 17 प्रमुख करों और 13 उपकरों को शामिल करते हुए पूरे भारत को एक बाजार में तब्दील किया गया।

क्या आप जानते हैं?
अप्रैल, 2023 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह **अब तक का सर्वाधिक** 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा जो साल दर साल जीएसटी राजस्व संग्रह से 12% अधिक है

आधार-डीबीटी लिंकेज- नागरिकों का सशक्तीकरण, शासन में सुधार

डीबीटी: लीकेज को हटाया

- 4.2 करोड़ नकली एवं जाली राशन कार्ड (2013-2021) को हटाया
- 4.11 करोड़ जाली/फर्जी/निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन समाप्त किये
- ग्रामीण विकास मंत्रालय में जाली/फर्जी/अपात्र लाभार्थियों को हटाया

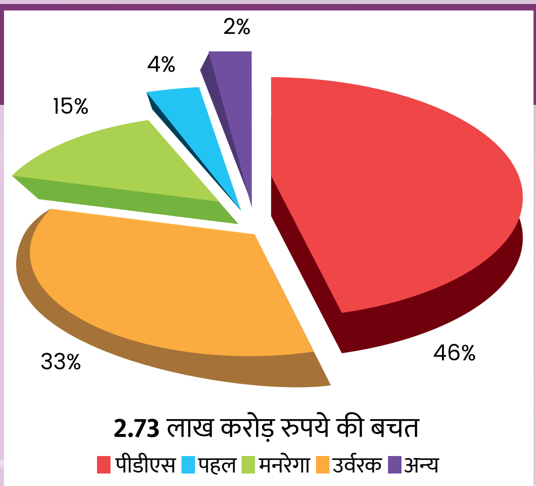

यूपीआई: देश का सबसे बड़ा एकल खुदरा भुगतान प्लेटफॉर्म

- यूपीआई से विश्व के 40% डिजिटल लेन-देन अब भारत में हो रहे हैं
- यूपीआई क्यू आर कोड में 4.6 गुना की बढ़ोतरी
- वित्त वर्ष 2022-23 में 8,371 करोड़ लेन-देन हुए जो 5 वर्षों में 91 गुना वृद्धि है
- वित्त वर्ष 2022-23 में 139.15 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन हुए जो 5 वर्षों में 126 गुना से अधिक वृद्धि है

जर्मन मंत्री भारत में डिजिटल पेमेंट करने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हुए

निर्यात: लोकल का ग्लोबल रुख

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात 776 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा

- वित्त वर्ष 2022-23 में मर्चेंडाइज निर्यात 451 अरब डॉलर पर अब-तक का सर्वाधिक रहा।
- सेवाओं का सबसे अधिक निर्यात पहली बार 325 अरब डॉलर रहा
- भारत के कृषि निर्यात ने वित्त वर्ष 2022-23 में 51 अरब डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर को हासिल किया
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 23.57 अरब डॉलर से अधिक दर्ज किया गया। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले इसमें 50.52% की वृद्धि हुई

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन
- 25.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत
- गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण
- जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए

स्टार्टअप इंडिया:

- भारत में अब 100 से अधिक यूनिकॉर्न
- वैश्विक स्तर पर हर 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत में
- 669 जिलों में स्टार्टअप को मान्यता दी गई
- अब तक 9.5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन
- वित्त वर्ष 2022-23 – मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा 2.7 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित

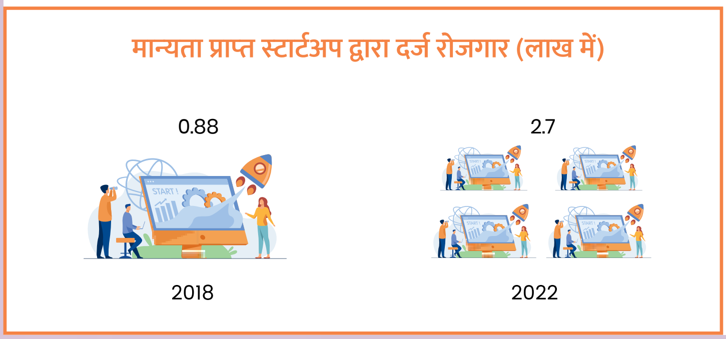

प्रधानमंत्री जन-धन योजना:
विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल

सबको बैंकिंग, सबको सुरक्षा और सबको वित्त पोषण

- 15 अगस्त 2014 को शुरुआत
- 34.26 करोड़ रुपे कार्ड जारी
- औसत जमा राशि 4,066 रुपये
- कुल 2.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा

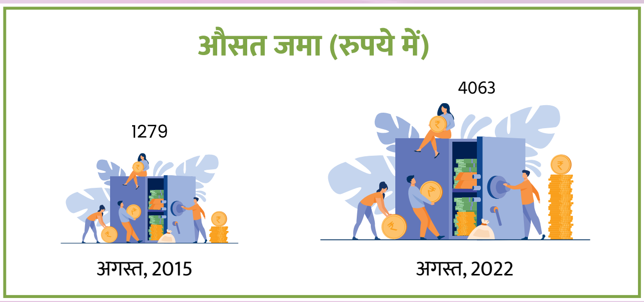

बैंक खाते: अगस्त, 2015 तक 17.9 करोड़, पीएम जेडीवाई के तहत 50.56 करोड़ खाते खुले

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पहली बार जीरो बैलेंस अकाउंट्स खोले गए

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस:

- समावेशन, उपयोगिता, पारदर्शिता, दक्षता और लागत में बचत
- पोर्टल ने 4.91 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वार्षिक खरीद दर्ज की (जुलाई, 2023 तक)
- ऑर्डरों की संख्या 1 करोड़ के पार, जिसमें से 55 प्रतिशत ऑर्डर मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्योग से (जुलाई, 2023 तक)
- जेम (GEM) पर 8 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्योग सेवा प्रदाता पंजीकृत

GeM
Government
e Marketplace

Efficient • Transparent • Inclusive

व्यापार सुगमता

"एक समय था जब कहा जाता था - Why India. अब जो Reforms देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है- 'Why not India'" – **नरेन्द्र मोदी**

देश में व्यापार सुगमता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने हरसंभव प्रयास किए हैं। अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने और पारदर्शिता पर जोर देने के साथ ही विभिन्न कानूनों एवं विनियमों के सरलीकरण से उल्लेखनीय बदलाव आया है।

- कानूनों के बोझ से मुक्ति: 41,000 से अधिक अनुपालन समाप्त कर दिए गए
- कंपनी कानून और एलएलपी कानून से संबंधित प्रावधानों का गैर–अपराधीकरण: 2017 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया और कई प्रावधानों को गैर–अपराधीकृत बना दिया गया और नागरिक त्रुटियों के रूप में माना गया
- कंपनियों पर कर का बोझ घटा: घरेलू कंपनियों के लिए अधिभार सहित प्रत्यक्ष कर को 30 प्रतिशत से घटाकर अधिभार और उपकर सहित 25.17 प्रतिशत कर दिया गया

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

एफडीआई (अरब डॉलर में)

पीएलआई योजना

- भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना
- अगले 5 साल के दौरान 14 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता
- 60 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य

स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को मजबूती

- 100 से अधिक यूनिकॉर्न का उद्भव

समय में बचत

- नियामकीय मंजूरियां/ प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए वन-स्टाप डिजिटल प्लेटफॉर्म
- निवेशकों की मदद के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस)

प्रक्रियाओं में आसानी

- कंपनी इनकॉरपोरेशन के लिए सरल एकल वेब एसपीआईसीई प्लस और एजाइल-प्रो-एस
- 41,000 से अधिक अनुपालनों को हटाया गया

नीतिगत सुधार

- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2022
- एफडीआई निवेश को बढ़ावा
- भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) को लागू करना
- अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम लागू। अधिनियम में 19 मंत्रालयों/विभागों से जुड़े 42 केंद्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया/तर्कसंगत बनाया गया

औद्योगिक गलियारा

- भारत में नए औद्योगिक नोड्स का विकास
- 11 औद्योगिक गलियारे का विकास

सीमा पार व्यापार में सुगमता

- इंडिया कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईजीएटीई) के जरिये दस्तावेज़ों को तेजी से मंजूरी

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रगति पथ

> "जब आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है।"
>
> – **नरेन्द्र मोदी**

पीएम गतिशक्ति— प्रगति को रफ्तार

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी
- नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुगमता
- वस्तु एवं सेवाओं की आवाजाही में लागत और समय की बचत
- बुनियादी ढांचे के विकास के साथ रोजगार सृजन

सड़क, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग, बंदरगाहों का विस्तार

कनेक्टेड भारत का निर्माण

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क (किलोमीटर में)

91,287

1,46,145

1 अप्रैल, 2014

वर्तमान में

पिछले 10 वर्षों में 54,858 किलोमीटर की वृद्धि

निर्मित सड़क की लंबाई (किलोमीटर में)

2013-14 से 2020-21 के दौरान 3 गुना वृद्धि

प्रति दिन निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई (किलोमीटर में)

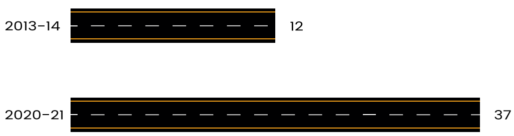

2013-14 से 2020-21 के दौरान निर्माण की गति में 3 गुना वृद्धि

3,81,135

7,46,448

मार्च 2014 तक

अक्टूबर 2023 तक

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क (किलोमीटर में)

यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर

- 'यशोभूमि' को लगभग 5400 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है।
- 11000 प्रतिनिधियों से अधिक की बैठने की क्षमता के साथ एक भव्य कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं।
- बैठने की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल आगंतुकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगा।
- कन्वेंशन सेंटर देश के सबसे बड़े एलईडी मीडिया अग्रभाग से सुसज्जित है।
- 'यशोभूमि' दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में से एक।

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (यशोभूमि) का लोकार्पण किया

परिवहन परिवेश में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

फास्टैग

फास्टैग ई-टोलिंग

889 राष्ट्रीय और 339 राज्य राजमार्ग शुल्क प्लाजा अब फास्टैग से जुड़े

रेलवे में प्रमुख उपलब्धियां

- वंदे भारत एक्सप्रेस – 2019 में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन।
- देश में फिलहाल अलग-अलग रूट पर 68 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित।
- अगले 3 वर्षों में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों का विनिर्माण किया जाएगा। यह 'मेक इन इंडिया' का अभूतपूर्व उदाहरण है।

मेट्रो रेल में 'मेक इन इंडिया'

- 2014: 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का परिचालन
- 2023: 20 शहरों में 878 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का परिचालन

विमानन क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां
2023
742 विमान
149 हवाई अड्डे
2014
400 विमान
74 हवाई अड्डे

अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में 30 दिसंबर, 2023 को महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अन्य नेतागण

आम नागरिकों की हवाई यात्रा का सपना पूरा

1.28 करोड़ से अधिक लोगों ने की हवाई यात्रा

11 ऑपरेटरों ने 2.43 लाख उड़ानों का संचालन किया

75
हवाई अड्डे

489
मार्ग

*23 सितम्बर, 2023 तक

भारत का टेक्नोलॉजी युग

"हम भारत में आधुनिक डिजिटल अवसंरचना तैयार कर रहे हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे"

- नरेन्द्र मोदी

चंद्रयान-3 मिशन

- भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना
- लागत प्रभावी अंतरिक्ष अभियानों में भारत ने अपनी क्षमता साबित की
- चंद्रयान–3 की सफलता में महिला वैज्ञानिकों ने बड़ी भूमिका निभाई
- चंद्रयान–3 का मुख्य ध्यान चंद्रमा की सतह की विशेषताओं का एक एकीकृत मूल्यांकन प्रदान करना रहा, जिसमें चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी (रेगोलिथ) के साथ ही चंद्रमा की सतह के तापीय गुण और उसकी सतह के निकट प्लाज्मा वातावरण के तत्व शामिल हैं
- चंद्रयान–3 के लैंडिंग बिंदु को 'शिव शक्ति बिंदु' और चंद्रयान–2 के पदचिह्न को 'तिरंगा बिंदु' नाम दिया गया
- चंद्रयान–3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के रूप में मनाया जाएगा

आदित्य एल 1 मिशन

प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान-3 मिशन में शामिल इसरो की महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात की

- सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष–आधारित भारतीय मिशन
- इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा
- आदित्य एल1 सूर्य की कोरोनल हीटिंग, मास इजेक्शन और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा

गगनयान मिशन

- **गगनयान मिशन भारतीय प्रक्षेपण यान पर पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन संचालित करने की क्षमता प्रदर्शित करेगा**
- **2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने का लक्ष्य**
- **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्थापित करने का लक्ष्य**

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

क्या आप जानते हैं ?

भारतनेट के तहत 1.98 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

टैक्नोलॉजी

टैक्नोलॉजी मेरे लिए खोज, सीखना, विकसित करना व क्रियान्वित करना है। यह गति के साथ सेवा को सरल बनाती है। टैक्नोलॉजी तेज, सरल तथा लोगों की सेवा करने का एक शानदार तरीका है।

श्री नरेन्द्र मोदी

ई-गवर्नेंस और सेवाओं की सुगमता

- मई, 2023 तक देश भर में 5.21 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालित; इनमें से कुल 4.13 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं
- रुपे कार्ड के माध्यम से भारत के पहले वैश्विक भुगतान तंत्र में 70 करोड़ भारतीय शामिल
- उमंग ऐप – 905 केंद्र और राज्य सरकारी विभागों की 877 सेवाएं उपलब्ध
- किसान रथ मोबाइल एप्लिकेशन (कृषि उपज के परिवहन के लिए किराए पर वाहन लेने के लिए 5.84 लाख किसान, किसान संगठन, व्यापारी और सेवा प्रदाता पंजीकृत
- मिशन की प्रगति को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए SBM 2.0 MIS ऐप विकसित किया गया। ऐप SBM Ph II के तहत संपत्ति के डेटा को अपलोड करने की अनुमति देता है। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियों को जियो–टैग किया गया है

Digital India
Power To Empower

नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 1.17 करोड़ मानचित्रों को डिजिटल किया गया। 94.23 प्रतिशत गांवों के भूमि अभिलेख कंप्यूटर में दर्ज
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 4.6 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया

सेमीकॉन इंडिया 2023: भारत बन रहा सेमीकंडक्टर का उभरता हब

- भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक वित्तीय प्रोत्साहन
- सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स और अन्य केंद्रों को स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50% तक समान वित्तीय सहयोग
- यह दस साल की अवधि में भारत की जीडीपी में 60,000 से 70,000 करोड़ रुपये जोड़ेगा

नॉर्थ-ईस्ट विकास का नया इंजन

“आज नॉर्थ-ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं,
बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं।”

– **नरेन्द्र मोदी**

शांति और समृद्धि के लिए समझौते

एनएलएफटी (एसडी) त्रिपुरा शांति समझौता
2019

ब्रू पुनर्वास समझौता
2020

बोडो शांति समझौता
2020

कार्बी आंगलोंग शांति समझौता
2021

एनएससीएन (आईएम) के साथ बुनियादी समझौता
2015

आदिवासी असम शांति समझौता
2022

पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

- पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम–डिवाइन) का बजट 2022–23 में ऐलान; 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन
- ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी और हथसिंगिमारी, नेमातिया और कमलाबाड़ी एवं गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच रो–रो सेवा की शुरुआत
- असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल के पास बोगीबिल रेल–सह–सड़क पुल उत्तर और दक्षिण किनारों पर लिंक लाइनों (लंबाई–73 किमी) के साथ दिसंबर 2018 में पूरा हुआ– 5,920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत
- 2014 से पहले उत्तर–पूर्व में केवल 9 हवाई अड्डे थे, पिछले नौ साल में उत्तर–पूर्व में 7 नए एयरपोर्ट बने
- मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पर पहली बार मालगाड़ी पहुंची
- मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनें मिलीं
- पूर्वोत्तर में 146.559 किमी की लंबाई की 121 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं 18.628 किमी की 25 सुरंगें परिचालन में हैं
- पूर्वोत्तर को आरसीएस–उड़ान के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है, स्कीम के तहत इंफाल–दीमापुर, शिलांग–कोलकाता; दीमापुर–गुवाहाटी, कोलकाता–लीलाबाड़ी; गुवाहाटी–लीलाबाड़ी; आदि विभिन्न आरसीएस मार्ग शुरू
- पूर्वोत्तर की कई जगहों जैसे तुइरियल, पारे और कामेंग में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण
- लोवर सुबनसिरी पनबिजली परियोजना का निर्माण

विरासत और विकास

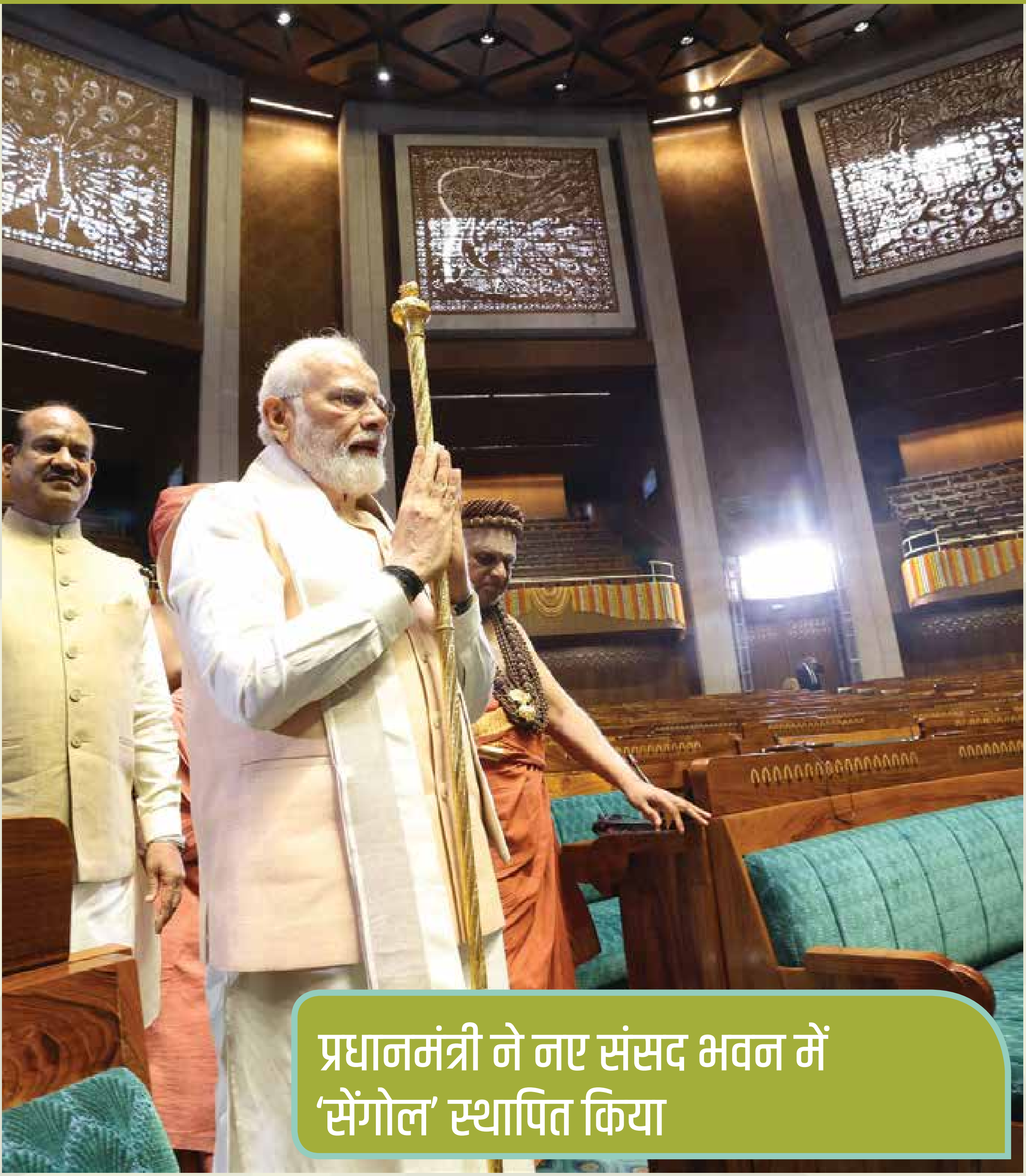

प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में
'सेंगोल' स्थापित किया

भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात

डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक
नई दिल्ली

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा
कर्तव्य पथ, नई दिल्ली

जलियांवाला बाग स्मारक

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित 'जनजातीय गौरव दिवस'

- स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों की स्वतंत्रता से जुड़ी भूमिका प्रदर्शित करने के लिए कोलकाता में स्थापित बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन
- सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के लिए 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' का नई दिल्ली में निर्माण

- गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित करने के प्रयास में देश ने 2022 को लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में मनाया। लचित बोरफुकन (24 नवंबर, 1622 – 25 अप्रैल, 1672) असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल थे, जिन्होंने मुगलों को हराया और औरंगजेब के अधीन मुगलों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक रोका।

भारत मंडपम

“‘भारत मंडपम’ आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। ‘भारत मंडपम’ दर्शन है, भारत की भव्यता का और भारत की इच्छाशक्ति का।”

— **नरेन्द्र मोदी**

- **भारत मंडपम की उत्पत्ति भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम के विचार से हुई है, जो सार्वजनिक समारोहों के लिए एक मंडप था**
- **सम्मेलन केंद्र भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है**
- **भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति 27 फीट ऊंची है और इसका वजन 18 टन है। यह अष्टधातु से बनी सबसे ऊंची मूर्ति है।**

सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी के रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए

प्राचीन काल की धरोहरों को वापस लाया गया

- 2014 से अब तक प्राचीन काल की 238 अनमोल मूर्तियों को सफलतापूर्वक लाया गया

सांस्कृतिक स्थलों का विकास

महाकाल लोक कॉरिडोर

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर

अयोध्या धाम

केदारनाथ धाम

सोमनाथ

विशेषांक

पर्यावरण और सतत विकास

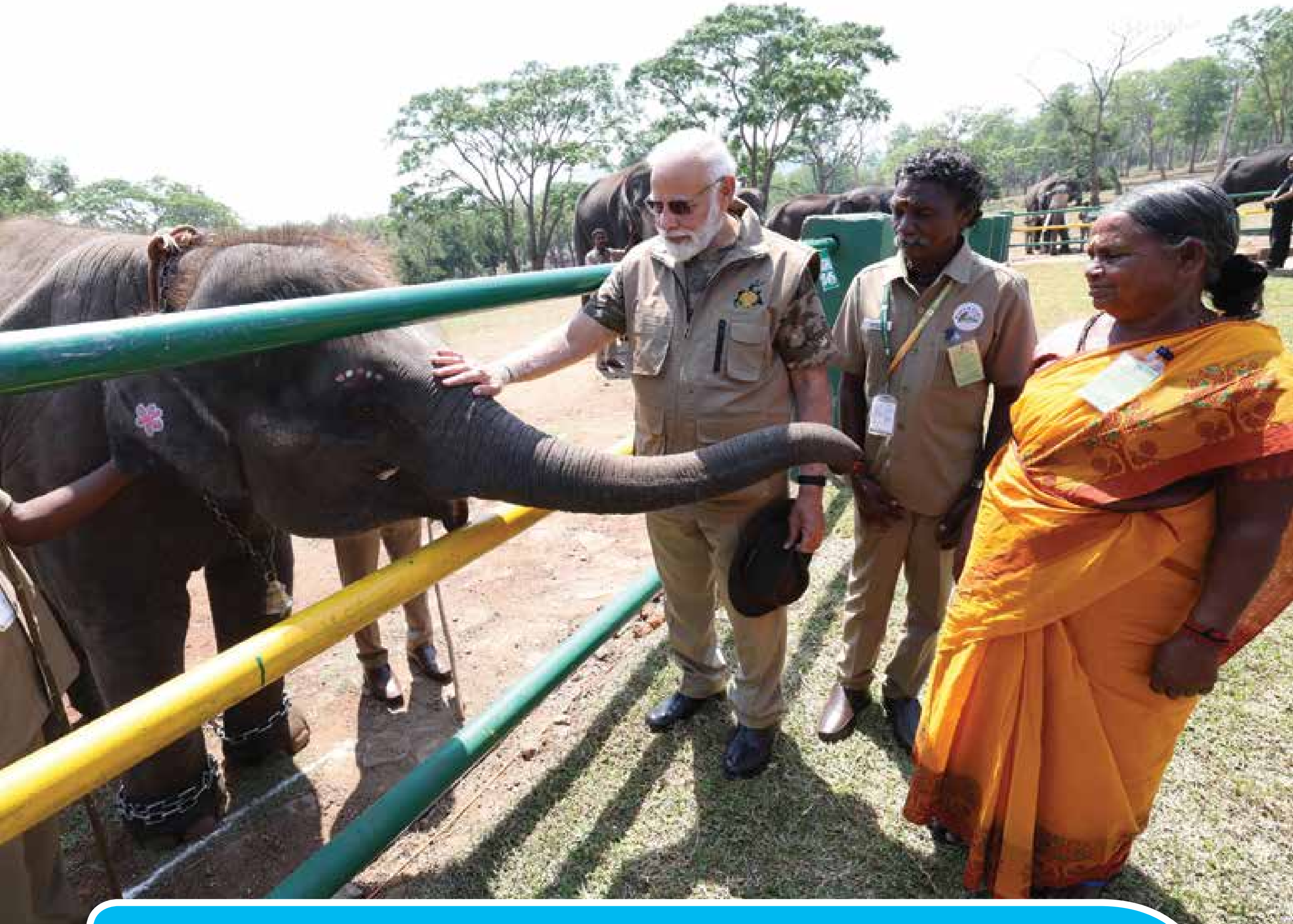

> "भारत प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।"
>
> – **नरेन्द्र मोदी**

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन: जी–20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल
- इस गठबंधन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है
- यह गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा

अक्षय ऊर्जा में भारी वृद्धि

- अक्षय ऊर्जा (आरई) की स्थापित क्षमता में पिछले नौ वर्षों में 2.37 गुना की वृद्धि
- भारत अब स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है
- सौर ऊर्जा क्षमता 2014 से सितंबर, 2023 के बीच 2.63 गीगावॉट से बढ़कर 71.78 गीगावॉट से अधिक हुई, सौर पार्क योजना 20 गीगावॉट से दोगुना बढ़कर 40 गीगावॉट हुई। दरों में 1.99 रुपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड निचला स्तर प्राप्त।
- 2030 तक 5 अरब टन ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के प्रति वर्ष उत्पादन में सहायता के लिए 15 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।

गोबर-धन योजना

- गोबर–धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो–एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना को औपचारिक रूप से 30 अप्रैल, 2018 को एसबीएम (जी) के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया।
- गोबर–धन भारत सरकार की सर्कुलर इकोनॉमी और 'मिशन लाइफ' अभियान के अनुरूप 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल है।
- ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि गोबर और ठोस कृषि कचरा को खाद और बायोगैस में परिवर्तित करके जैव–अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करने और धन और ऊर्जा पैदा करने के लिए सामुदायिक परियोजनाओं की स्थापना की जाए।
- एसबीएम (जी) के दूसरे चरण में सामुदायिक गोबर–धन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति जिला 50 लाख रुपये तक का प्रावधान है। एसबीएम (जी) के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति जिला कम से कम 1 गोबर–धन संयंत्र अनिवार्य है।

गोबर - धन
(गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज - धन)

मवेशी तथा जैविक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए जन आंदोलन

796
जैव-गैस/सीबीजी प्लांट - पूर्ण/क्रियाशील

424
जैव-गैस/सीबीजी प्लांट - निर्माणाधीन

443
जिले जैव-गैस के तहत + 132 जिले सीबीजी के तहत

जिले जहां प्रोजेक्ट की स्थिति पूर्ण/कार्यशील

उजाला योजना

- सभी को सस्ती दरों पर एलईडी (उजाला) के उद्देश्य से 2015 में लॉन्च
- दुनिया का सबसे बड़ा गैर-सब्सिडी वाला स्वदेशी प्रकाश व्यवस्था का कार्यक्रम
- भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एलईडी बाजार है

राष्ट्रीय उजाला डैशबोर्ड

36,86,86,920

47,880 mn kWh	INR 19,152 Cr	9,586 MW	3,87,83,081 t CO_2
प्रति वर्ष ऊर्जा को बचाया	प्रति वर्ष लागत की बचत	अधिक मांग की अनदेखी	CO_2 प्रति वर्ष में कमी

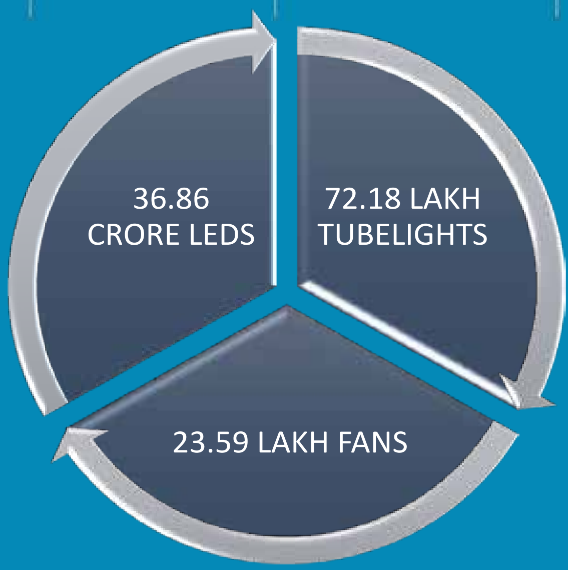

क्या आप जानते हैं?

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उजाला से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति वर्ष 16 अरब रुपये से अधिक की बचत हुई है

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना

- अन्नदाता को ऊर्जादाता में बदलने के लिए फरवरी, 2019 में प्रारंभ
- सौर ऊर्जा चलित कृषि पंप के माध्यम से 35 लाख से ज्यादा किसानों को ऊर्जा

10,000 मेगावॉट के सौर/ अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित

20 लाख सौर कृषि पंप लगाए गए

ग्रिड से जुड़े **15 लाख** कृषि पंप सौर ऊर्जा चलित बनाए गए

एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड

- अक्टूबर, 2023 तक स्थापित सौर क्षमता 71.78 गीगावॉट हुई
- एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड की अवधारणा को साकार करने के लिए वैश्विक ग्रिड बनाने का प्रयास जारी

मिशन लाइफ

प्रधानमंत्री ने दुनिया से 'पर्यावरण अनुरूप जीवन शैली' यानी LiFE को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक वैश्विक मिशन बनाने का आह्वान किया। इसका विजन न केवल ऊर्जा उत्पादन बल्कि ऊर्जा संरक्षण और बेहतर जीवन पर भी जोर देता है। इन समाधानों में ऊर्जा कुशल एसी, गीजर, हीटर और ओवन शामिल हैं।

नमामि गंगे

- गंगा नदी का कायाकल्प करने, प्रदूषण में प्रभावी कमी लाने और संरक्षण के लिए 2014 में प्रारंभ
- अब तक 37,985 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 448 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है; 260 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है

पीएम-ई-बस सेवा

- सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए 10,000 ई–बसें चलाई जाएंगी
- इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी
- इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है

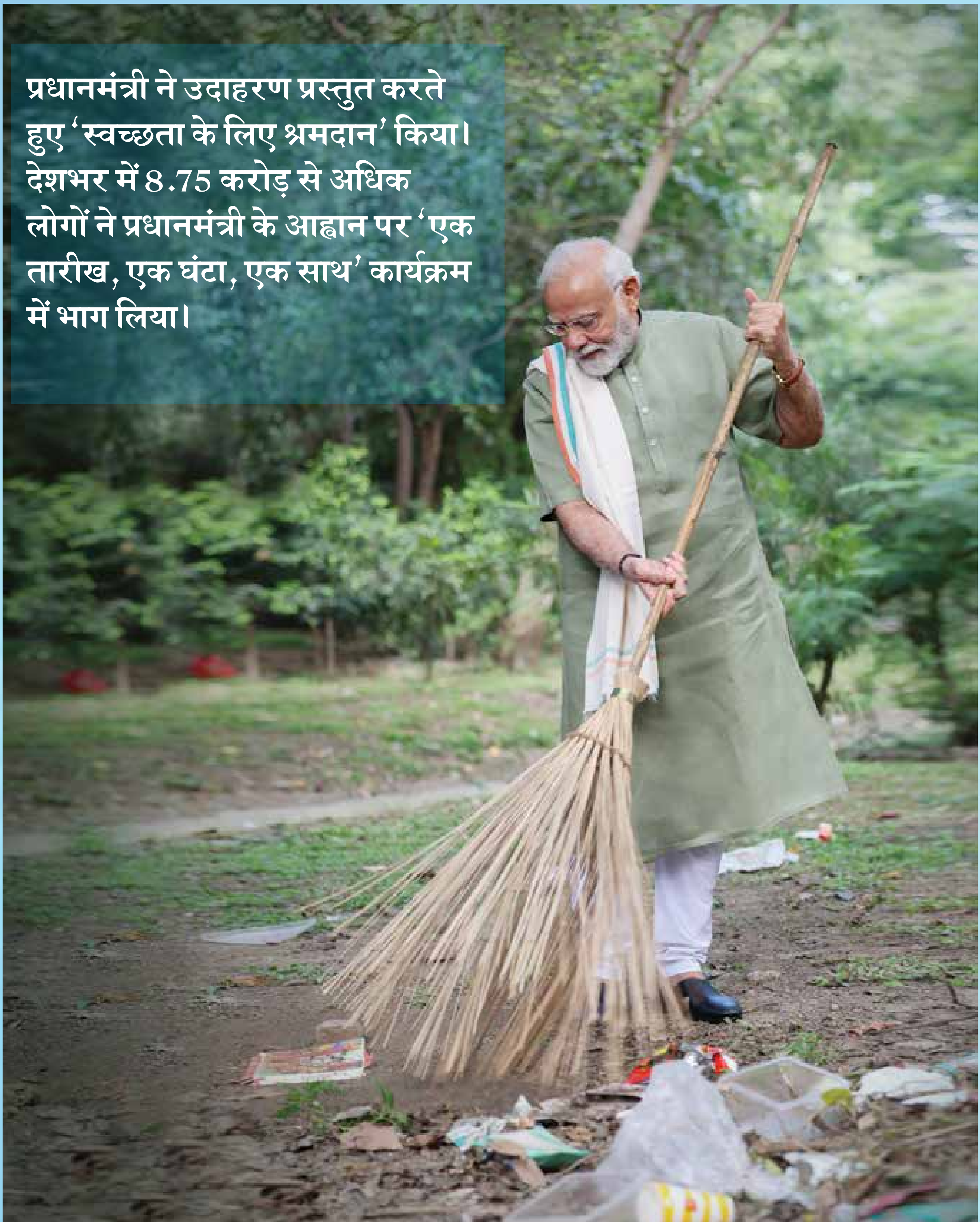

प्रधानमंत्री ने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 'स्वच्छता के लिए श्रमदान' किया। देशभर में 8.75 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' कार्यक्रम में भाग लिया।

भारतीय नेतृत्व को मिली वैश्विक सराहना

X@ **Joseph R. Biden Jr.**
President of the United States

One Earth. One Family. One Future.

That's the focus of this G20 Summit: building resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future that represents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone.

X@ **Rishi Sunak**
Prime Minister of the United Kingdom

Stronger together. Stronger united.
Thank you Narendra Modi for a historic G20 and the Indian people for such a warm welcome.

From global food security to international partnerships, it's been a busy but successful summit.

X@ **Giorgia Meloni**
Prime Minister of Italy

I thank the Prime Minister of India Narendra Modi for his stewardship of this Presidency #G20, which has put forward an ambitious agenda on global challenges. We have worked together to ensure the success of this Summit and we will continue to coordinate in bilateral relations and also in view of the Italian Presidency of the G7.

#G20India

X@ **Emmanuel Macron**
President of France

वसुधैव कुटुम्बकम्
The world is one family.
Le monde est une seule famille.

X@ **Anthony Albanese**
Prime Minister of Australia

A successful G20 meeting hosted by Narendra Modi in New Delhi today followed by a good bilateral discussion about concluding the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between Australia and India.

X@ **Ursula von der Leyen**

President of the European Commission

Thank you for your skillful leadership of the G20, @narandramodi.

A strong partnership with India is paramount for Europe. Glad to see our Trade & Tech Council in action. And to have launched with you an historic project, the India – Middle East – Europe Economic Corridor.

X@ **Bill Gates**

Co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation

The G20 reached a groundbreaking consensus on the role of digital public infrastructure as a critical accelerator of the Sustainable Development Goals. I'm optimistic about the potential of DPI to support a safer, healthier, and more just world. Kudos to PM Narendra Modi.

X@ **Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus**

Director-General, World Health Organization

We welcome the G20 Leaders' comprehensive commitment to health in the New Delhi Declaration, including to strengthen WHO. We will continue to work closely with G20 countries towards a healthier, safer, fairer future for all.

नई दिल्ली में 26 फरवरी, 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी के राष्ट्रव्यापी 'संकल्प पत्र सुझाव अभियान' एवं 'विकसित भारत – मोदी की गारंटी रथ' का शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)............................ (2).............................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.............................. दिनांक :.......................... बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो केंद्र (बेंगलुरु) में 27 अगस्त, 2023 को वैज्ञानिकों से जानकारी लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

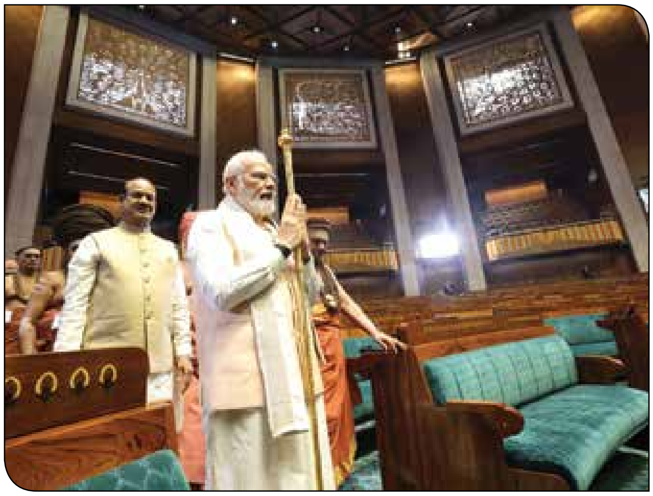

नई दिल्ली में 21 सितंबर, 2023 को नए संसद भवन में 'सेंगोल' स्थापित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला

जम्मू में 20 फरवरी, 2024 को विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह एवं अन्य नेतागण

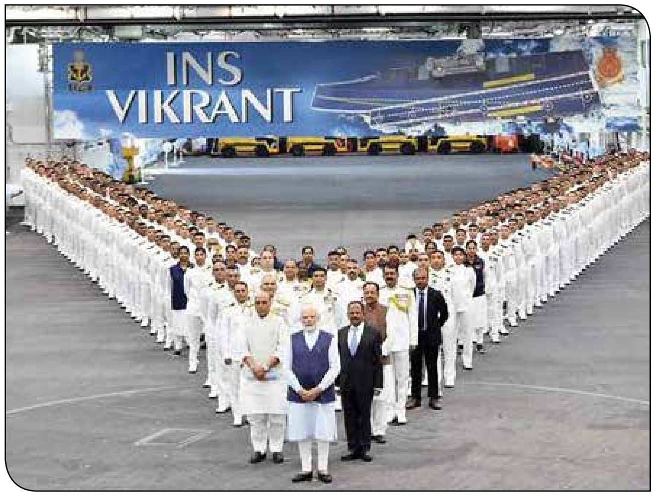

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 02 सितंबर, 2022 को कोच्चि, केरल में प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का किया जलावतरण

नई दिल्ली में 05 फरवरी, 2024 को संसद भवन में धार्मिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 11 जनवरी, 2024 को अपने आवास पर मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथिः (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघरः लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
76 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथिः 21 मार्च, 2024
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

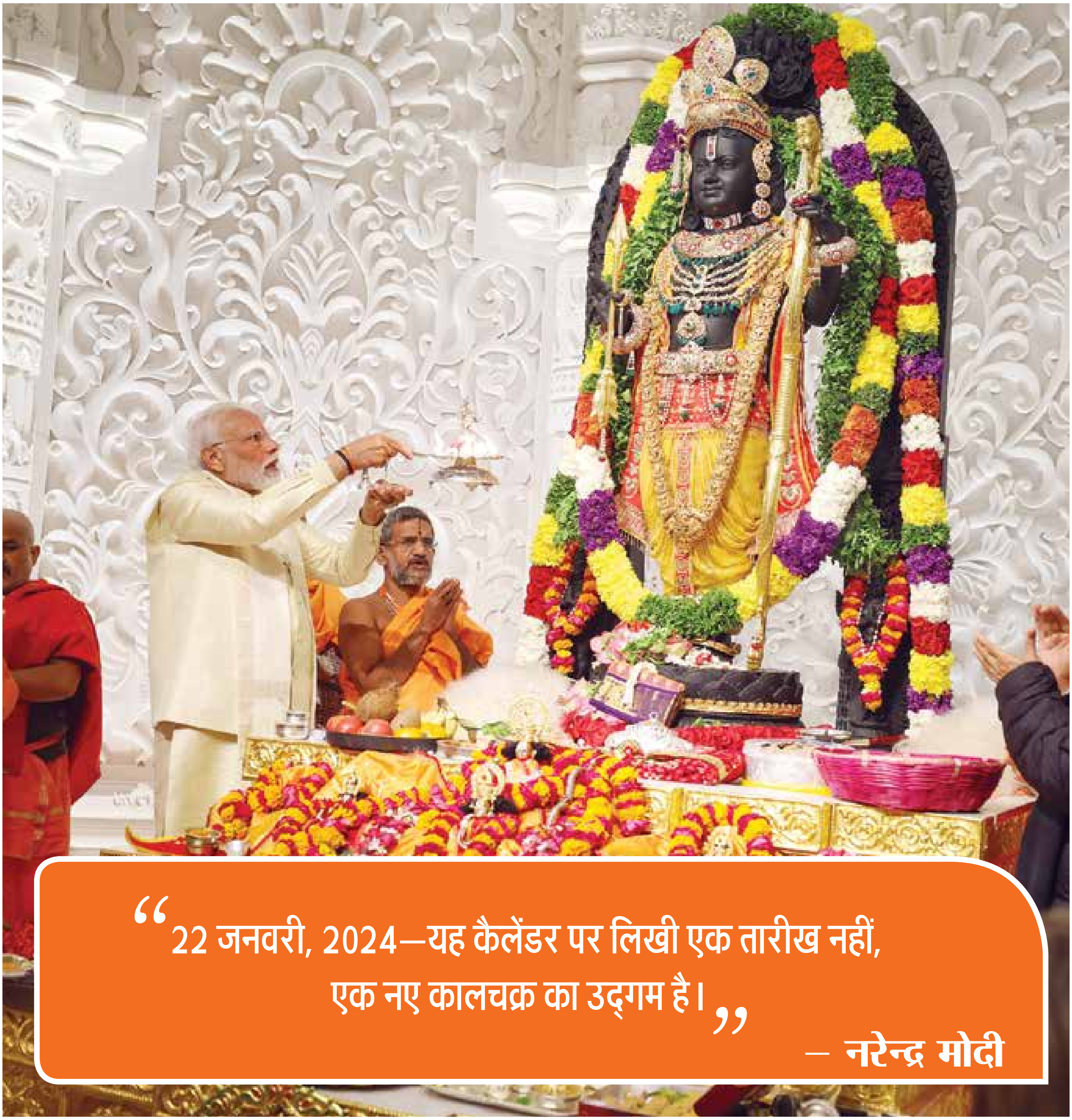

"22 जनवरी, 2024—यह कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं,
एक नए कालचक्र का उद्गम है।"

— **नरेन्द्र मोदी**

छायाकारः अजय कुमार सिंह